राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में दिनांक 19.03.2018 को आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त।

"नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की सातवीं बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ प्रोदिप्तो घोष की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2018 (सोमवार) को मध्याह्न 3.00 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई थी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने एक बार फिर नीति आयोग के सदस्य की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। सदस्य सचिव ने बताया कि टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने इस मामले पर नीति आयोग के सीईओ को दिनांक 27.02.2018 को एक डी.ओ. पत्र भेजा है और उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यस बैंक और श्री सतीश राव और डॉ दासगुप्ता इस बैठक में समूह को प्रस्तुतियां देंगे।इसके बाद उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वे कार्यसूची मदों को एक-एक करके चर्चा के लिए उठाएं।

मद 7.1: 27.02.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय पहलुओं पर समूह की छठी बैठक के कार्यवृत्त को 16 मार्च, 2018 के पत्र के माध्यम से सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालित के रूप में की गई थी।

मद 7.2.1: राजकोषीय संसाधनों के अनुमानों पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति

नीति आयोग के प्रतिनिधि के बैठक में शामिल नहीं हो पाने के कारण इस मद को एक बार फिर अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण की सीमा के साथ-साथ निजी क्षेत्र और बाहरी वित्तपोषण पर पड़ने वाले नीतिगत निर्णयों को जानने के लिए नीति आयोग की भागीदारी बहुत आवश्यक है। श्री के पी गुप्ता ने बताया कि कार्य बल के अध्यक्ष की ओर से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक डीओ पत्र भेजा गया है जिसमें वित्तीय समूह के विचार-विमर्श में नीति आयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

मद 7.2.2: भारतीय बैंकों / वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए धन के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति

श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, रणनीतिक सरकारी सलाहकार, यस बैंक, नई दिल्ली (श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यस बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने सूचित किया कि उन्होंने टेरी रिपोर्ट और मैकेंसी रिपोर्ट का अध्ययन किया है, लेकिन उक्त रिपोर्टों में वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वे अपनी प्रस्तुति को संशोधित नहीं कर सके जैसा कि बैठक में सुझाया गया था। अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनसे वांछित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

मद 7.2.3: समूह के अध्यक्ष और सदस्य श्री सतीश राव द्वारा आईएलआर और एमडीबी के लिए डीडीआर (सम्यक उद्यम आवश्यकताएं) पर प्रस्तुति

श्री सतीश राव, सदस्य ने आईएलआर वित्तपोषण के लिए सम्यक उद्यम आवश्यकताओं (डीडीआर) को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया

आईएलआर वित्तपोषण के लिए सम्यक उद्यम आवश्यकताएं (डीडीआरएस)

1. बैठक में आईएलआर वित्तपोषण के लिए सम्यक उद्यम आवश्यकताओं (डीडीआर) पर चर्चा की गई।
2. आईएलआर के वादे, लाभों, आशंकाओं और चुनौतियों के अवलोकन के साथ शुरू करते हुए, यह नोट किया गया था कि संबोधित किए जाने वाले सम्यक उद्यम आवश्यकताओं को एमडीबी से परे जाने और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं को भी शामिल करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, सम्यक उद्यम आवश्यकताओं को विभिन्न स्तरों पर संबोधित करने की आवश्यकता होगी: देश, क्षेत्र, राज्य, आईएलआर एक पूरे के रूप में और घटक, उप-परियोजना स्तर पर। इसके अलावा, आईएलआर में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की भागीदारी की कुंजी आईएलआर को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित प्रदर्शन (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और परियोजना क्षेत्रों में) की आवश्यकता हो सकती है:

(क) आपूर्ति, मांग और मांग-आपूर्ति अंतर/जल की कमी की वर्तमान स्थिति।

(ख) जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की मांग-आपूर्ति के अंतर/कमी का और अधिक बिगड़ना।

(ग) उत्तरी नदियों से दक्षिणी नदियों में जल के अंतरण के माध्यम से मांग-आपूर्ति संतुलन में सुधार लाना /घाटा कम करना।

(घ) वास्तव में, जलवायु परिवर्तन और फसल पैटर्न में परिवर्तन पर उचित विचार के साथ जल संसाधनों की आपूर्ति और मांग के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है, एक, आईएलआर के बिना और, दूसरा , आईएलआर के साथ ।

3. "अवलोकन" के बाद, बैठक एमडीबी-विशिष्ट डीडीआर पर चर्चा के लिए आगे बढ़ी जिसमें (i) आईएलआर के संबंध में संभावित चिंताएं शामिल हैं जो एमडीबी के सम्यक उद्यम आवश्यकताओं के प्रमुख भागीदार हो सकते हैं (ii) एमडीबी के डीडीआर के कवरेज और तीव्रता के प्रमुख निर्धारक, और (iii) एक एमडीबी स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट की उदाहरण सामग्री के आधार पर एक एमडीबी के विशिष्ट सम्यक डीडीआर: मुख्य पाठ, अनुलग्नक और तालिकाएँ।

चर्चाओं से निकालने वाले कुछ प्रमुख बिंदु :

संभावित बहुपक्षीय विकास बैंकों की चिंताएं:

i. बहुत बड़ा: बड़ी लागत, इसलिए मैक्रो आर्थिक प्रभाव प्रबंधनीय हैं? क्या अन्य क्षेत्रों /निवेशों में भीड़ नहीं होगी?

ii भौगोलिक रूप से कई राज्यों / प्रांतों में फैले हुए: क्या अंतर-राज्यीय सहमति संभव है? क्या यह स्थायी हो सकता है ?

iii. लंबे कार्यान्वयन की अवधि: केंद्रीय शासन में परिवर्तन से राजनीतिक जोखिम?

iv. बड़े पैमाने पर पानी का पथांतरण और भंडारण: व्यापक, अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव?

v. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास: पुनर्वास के मुद्दे? कार्यान्वयन में देरी? मुआवजा और अग्रिम निपटान?

vi. खराब लागत वसूली: वित्तीय स्थिरता वर्तमान लागत वसूली के स्तर पर व्यवहार्य नहीं है; प्रमुख परिवर्तनों की आवश्यकता है

vii उप-परियोजनाओं के बीच अंतर-निर्भरता के कारण जटिल: विभिन्न राज्यों / निष्पादन एजेंसियों के कारण सभी उप-परियोजनाओं में समय पर कार्यान्वयन मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण उप-परियोजनाओं की गति अनुचित रूप से धीरे हो सकती है

viii परियोजना से प्रभावित / गैर सरकारी संगठन / नागरिक समाज की आशंकाएं: महत्वपूर्ण होने की संभावना है, इसलिए परियोजना के पूरा होने और लागत में अतिरिक्त अनिश्चितता लाता है

सम्यक उद्यम आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए और तीव्रता के प्रमुख निर्धारक:

i. आईएलआर को एक-बड़े-क्षेत्रीय-एकीकृत परियोजना के रूप में पेश करना या कई छोटे-स्व-स्थायी-असतत उप-परियोजनाओं के रूप में

ii ऋण पद्धति: परियोजना ऋण / बहु-किश्त ऋण / क्षेत्र ऋण / कार्यक्रम ऋण

iii. एमडीबी की नीतियों, प्राथमिकताओं और उचित परिश्रम फोकस क्षेत्रों

iv. उप-परियोजना प्रस्तावों का दायरा और उद्देश्य

v. एमडीबी के उन लोगों से परे जाने वाले विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताएं

ग. निदर्शी एमडीबी कर्मचारी मूल्यांकन रिपोर्ट से निष्कर्ष**:** यह नोट किया गया था कि एमडीबी के विशिष्ट सम्यक उद्यम आवश्यकताएं काफी व्यापक हैं, जिनमें विषयों की व्यापक कवरेज और गहन विश्लेषण है।

4. उपर्युक्त के बाद, बैठक में नोट किया गया कि एमडीबी के डीडीआर को पूरा करने के लिए काफी तैयारी की आवश्यकता होगी। इस तरह की तैयारी के लिए उन संस्थानों की सेवाओं को नियोजित करने की आवश्यकता हो सकती है जो विभिन्न डीडीआर क्षेत्रों पर विस्तृत अध्ययन प्रदान कर सकते हैं।

श्री सतीश राव सदस्य ने इस समूह के आकलनकर्ता श्री एमके सिन्हा, केडब्ल्यूडीटी और विशेष आमंत्रित सदस्य से यह भी अनुरोध किया कि वे हिमालयी और प्रायद्वीपीय घटकों के 30 लिंकों को औचित्य के साथ विभिन्न समूहों/उप समूहों में वर्गीकृत करने के संबंध में राजविअ की ओर से एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण तैयार करें ताकि उन्हें प्राथमिकता दी जा सके और तदनुसार वित्तपोषण पैटर्न तय किया जा सके। श्री सिन्हा ने उल्लेख किया कि उन्होंने उप समिति (I) रिपोर्ट के लिए हिमालयी लिंकों के लिए इस प्रकार का अभ्यास किया है। तथापि, प्रायद्वीपीय घटक के लिए उन्हें कुछ राजविअ अधिकारियों की सहायता की आवश्यकता होगी। निदेशक (तक), राजविअ ने इस संबंध में आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया।

मद 7.3.1 और 7.3.2: समूह के कार्य की प्रगति की समीक्षा और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए।

(i) अध्यक्ष ने चर्चा के अंत में कार्यक्रम की समीक्षा की। अध्यक्ष को सूचित किया गया कि राजविअ ने पीपीपी मॉडल, एमडीबी की सम्यक उद्यम आवश्यकताओं, आईएलआर सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत आदि जैसे विषयों पर प्रस्तुति के लिए श्री विनायक चटर्जी से संपर्क किया। हालांकि किसी अन्य कार्य में अपनी संलग्नता के कारण, उन्होंने वित्त समूह की बैठकों में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की। लागत

आकलन के संबंध में अध्यक्ष ने संकेत दिया कि राजविअ को सौंपा गया कार्य पूरा हो गया है, तथापि, उन्होंने राजविअ को सुझाव दिया कि वह इस विषय पर लगभग 1000 शब्दों में एक लेखन तैयार करे जिसे समूह की मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है और श्री सतीश राव सदस्य को आईएलआर और एमडीबी के लिए डीडीआर (सम्यक उद्यम आवश्यकताएं) पर इसी तरह का लेखन तैयार करने के लिए तैयार किया जाए।

चर्चा के बाद, अगली बैठक के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर सहमति व्यक्त की गई:

(ii) नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति

(iii) यस बैंक द्वारा प्रस्तुति

(iv) डॉ. गोसाईं, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर को "आईएलआर परियोजना की घोषणा की संभावना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शमन और उस पर देय विभिन्न आवश्यकताओं" पर प्रस्तुति देने के लिए अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया था।

मद 7.4 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला।

सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ चर्चा के बाद 10 अप्रैल, 2018 को समूह की अगली बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 19 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की सातवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ प्रोदिप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और टेरी के प्रतिष्ठित फेलो,नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एच सतीश राव, (सेवानिवृत्त) महानिदेशक, एडीबी, बंगलुरु	सदस्य
3.	श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी, फरीदाबाद	सदस्य
4.	श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, रणनीतिक सरकार सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री बी पी पांडे, निदेशक, आईएसएम, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	मुख्य अभियंता (आईएमओ) का प्रतिनिधित्व करते हुये
6.	श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तक), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
7.	श्री दीपक दास गुप्ता, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री एम के सिन्हा, मूल्यांकनकर्ता, कृष्णा जल विवाद अधिकरण और (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य

9.	श्री आर पी एस वर्मा, निदेशक (एनपी), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित, मुख्य अभियंता (पीपीओ), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए
	अन्य अधिकारी	
10.	श्री अनिल कुमार जैन, उप-निदेशक (एससीआईएलआर), राजविअ, नई दिल्ली	
11.	श्री आर के अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ,नई दिल्ली	
12.	श्री वैभव जैन, वरिष्ठ प्रबंधक-स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट सलाहकार , यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	